(b) the details of the proposals worked out till date in this regard; and

(c) by when these proposals are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) Initiatives taken by Government to reform almost all areas of industrial activity viz. industrial policy, foreign investment, trade and exchange rate regime, fiscal policy, capital market, financial sector are aimed at encouraging entrepreneurship, allowing free flow of foreign investment, promoting modernisation and technological upgradation to bring reduction in costs, improve efficiency, productivity and enhance competitiveness of the industry with a view to boost industrial production and exports. Tax rates for domestic companies were reduced to 40% in the Union Budget 1994-95. The surcharge of 15% on the income tax of a domestic company, if its total income exceeds Rs. 75000 has not been removed due to revenue considerations. Investment incentives have been extended in the form of tax holiday to new industrial units in infrastructure sector, power and in backward States.

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निर्यातों में वृद्धि

8228. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठ मलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में निर्यात मूल्य के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत बढ़ा है ;

(ख) यदि हां तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों में देश के निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र में किये गये निर्यात का अलग-अलग प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए उपर्युक्त वर्षों के दौरान समय समय पर बहुत से प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्या क्या प्रोत्साहन कब कब घोषित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिशत भाग में 1992-93 में 1993-94 की तुलना में वृद्धि हुई है । वर्ष 1994-95 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) निर्यात आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	कुल निर्यात में लघु उद्योग का प्रतिशत भाग
1992-93	33.34
1993-94	36.38
1994-95	अभी उपलब्ध नहीं ।

(ग) और (घ) सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ दे रही है :—

(1) चुनिंदा लघु उद्योग एककों को विदेश में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रायोजित किया जा रहा है । स्थान सम्बन्धी किराये भाड़े, बीमा, प्रति वस्तुओं की हैन्डलिंग और क्लेरियंग संबंधी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्यापार संबंधी पूछताछ को लघु उद्योग के निर्माताओं के लाभकारी इस्तेमाल / वाणिज्यिक समझौता के लिए अखिल भारतीय आधार पर परिचारित किया जाता है। चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सीडो की भागीदारी 1985 से शरू हुई ।

(2) निर्यात के लिए पैकेजिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किये जाते हैं ताकि लघु उद्योग निर्यातकों को नवीनतम पैकेजिंग मानकों/तकनीकों से वाकिफ कराया जा सके । ये कार्यक्रम भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से आयोजित किये जाते हैं जो इस संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं । यह विशेष एवं सामान्य उद्योग के कार्यक्रम हैं । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1978–79 से शुरू किये गये थे ।

(3) सरकार लघु उद्योग विनिर्माताओं/सत्ता निर्यातकों को तकनीकी एवं सत्ता प्रदान कर रही है ।

(4) सरकार ने गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है जो कि लघु उद्योग विनिर्माताओं को देश में गुणवत्ता की जागरुकता को बढ़ाने के लिये दिया जाता है । यह पुरस्कार गुणवत्ता वाले उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा और जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा । ये पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू किये गये थे ।

(5) आयात निर्यात नीति के तहत निर्यात गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह/सुपर व्यापार गृह के रूप में मान्यता देने के लिये अतिरिक्त बल लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात पर दिया गया है ।

(6) इस के अतिरिक्त निर्यात आयात नीति 1992–97 में दिये गये प्रोत्साहन उद्योग निर्यातकों के लिये भी उपलब्ध हैं ।

Restructuring of BICP

8229. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any final view has been taken in the matter of restructuring of Bureau of Industrial Costs and Prices;

(b) if so, the details thereof;

(c) the recommendations made by the group appointed in this behalf; and

(d) the action taken by Government on the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (d) Government has not taken any final decision in the matter of restructuring of the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). Government has not appointed any group in this behalf.

Persons benefited under P.M.'s Rozgar Yojna in Madhya Pradesh

8230. SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of youth benefited under the Prime Minister's Rozgar Yojna in Madhya Pradesh as on the 31st March, 1995, district-wise;

(b) what is the total amount released to the State so far under the Prime Minister's Rozgar Yojna (PMRY) since its inception;

(c) whether Government are aware that Banks are not releasing in time the amount sanctioned to the youth under the Yojna in the State; and

(d) if so, what remedial steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Under Prime Minister's Rozgar Yojana, 21840 persons were sanctioned loan during 1993-94 and 1994-95 respectively. District-wise details as furnished by the State Government is enclosed in Statement (See below).